बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–18.07.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में मॉनसून 2016 के दौरान उत्पन्न बाढ़ एवं अल्प वर्षापात की स्थिति से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. विकास आयुक्त, बिहार
2. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,
3. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग
4. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
6. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
7. प्रधान सचिव, कृषि विभाग
8. प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग
9. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
10. प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
11. सचिव, स्वास्थ्य विभाग
12. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
13. आयुक्त, पटना नगर निगम
14. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
15. निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
16. संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
17. विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम

IMD के स्थानीय निदेशक के द्वारा बताया गया कि 17 जुलाई तक –14% वर्षापात हुआ है। अगले तीन दिनों में वर्षापात की ये कमी भी दूर हो जाएगी। अगले तीन सप्ताह में उत्तरी बिहार में Moderate to Heavy Rainfall की संभावना है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वर्षापात के आंकड़े का स्रोत CWC एवं अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त आंकड़े भी होते हैं। मुंगेर जिले में मात्र दो observatory हैं, जिसके कारण मुंगेर जिला में वर्षापात का आंकड़ा 15 mm परिलक्षित हो रहा है। निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा बताया गया कि उनके पास मुंगेर जिले में नौ स्थानों से वर्षापात के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय प्रतिदिन 12 बजे तक सभी जिलों का आंकड़ा IMD को उपलब्ध करा दे। अगर

IMD तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़ों में अधिक भिन्नता हो तो उसी दिन दूरभाष से संबंधित जिले से संपर्क कर, भिन्नता का कारण ज्ञात कर, समाधान कर लिया जाए।

2. <u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रधान सचिव, जल संसाधन द्वारा बताया गया कि गंडक में Heavy Discharge (200000 क्युसेक से ज्यादा) के कारण गोपालगंज के तरफ तटबंधों पर दबाव है, जिसकी निगरानी की जा रही है। गोपालगंज जिले के पतराहा छड़की पर दबाव है। सभी जलाशयों में पानी की स्थिति ठीक है। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 170000 क्यूसेक जलश्राव हो रहा है। इस अधिक जलश्राव के बावजूद भी तटबंध सुरक्षित है। कोसी नदी के जलस्तर से कटाव कम होना बताया गया।

मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि तटबंधों की सतत् निगरानी की जाए।

3. <u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि पटना शहर में वर्षापात से जल जमाव मात्र पटना रेलवे स्टेशन पर है। यह स्थिति पुल निर्माण निगम द्वारा पुल निर्माण के क्रम में नाला तोड़ दिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। इसके निदान हेतु आज 3.00 बजे अपराह्न को बैठक आयोजित की जा रही है। पटना के सभी सम्प हाऊस चल रहे हैं।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि पटना रेलवे स्टेशन पर नाले की निर्माण की कार्रवाई शीघ्र कराई जाए।

4. <u>कृषि विभाग</u>

प्रधान सचिव कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि धान का अच्छादन 19.36% हुआ है और धान के बिचड़े का आच्छादन 93.46% हुआ है। सिवान जिले के प्रभारी सचिव श्री जितेन्द्र श्रीवस्तव द्वारा बताया गया कि वहाँ करीब 90 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से गंडक परियोजना से 45000 हेक्टेयर भूमि ही सिंचित हो पाता है। शेष क्षेत्रों में डीजल पंपिंग सेट से सिंचाई संभव है। उनके द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि किसानों के स्व अभिप्रमाण पर डीजल अनुदान देने की कार्रवाई की जा सकती है।

मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उपयुक्त सुझाव पर विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाए।

5. <u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि 500–600 नए चापाकल जरूरत के अनुसार क्षेत्रों में लगाया जाएगा। प्रधान सचिव, आपदा

प्रबंधन द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके जिले के कुछ स्थानों पर जल स्तर करीब 35' नीचे चला गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा बताया गया है कि वहाँ टैंकर से पानी भेजवाने की कार्रवाई की जा रही है एवं नए चापाकल गड़वाया जा रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ जल स्तर नीचे चला गया है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति की जाँच कर ली जाए तथा उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

6. सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा बताया कि केन्द्रीय फसल बीमा योजना, जिसमें Premium का 50% राशि भारत सरकार द्वारा तथा शेष राज्य सरकार द्वारा दिया जाना है। इस संबंध में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश के लिए 4% Premium रखा गया है और बिहार सरकार के लिए 12% Premium रखा गया है।

मुख्य सचिव महोदय ने निदेश दिया गया कि Premium की राशि के इस अंतर के संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र भेजा जाए।

7. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

सांख्यिकी निदेशालय द्वारा बताया गया कि प्रखण्डों से उन्हें वर्षापात का डाटा प्रतिदिन प्राप्त होता है, जिन्हें वे कृषि विभाग के साथ साझा करते हैं।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि मॉनसून के दौरान डाटा प्रति दिन अद्यतन किया जाए। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग एवं IMD को वर्षापात का प्रतिदिन का डाटा 12 बजे तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए।

8. पशु एंव मत्स्य संसाधन विभाग

प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में पशु चारा की कोई समस्या नहीं है। पशु चारा का दर निर्धारित किया जा चुका है। पशुओं की दवाई का क्रय जिला स्तर पर की जा रही है। पशुओं के लिए टीका की खरीद के लिए निदेशालय स्तर पर निविदा निकाला गया है।

मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वर्षापात के दौरान होने वाले पशु के रोगों से संबंधी टीका का क्रय शीघ्र कर टीकाकरण की कार्रवाई की जाए।

9. स्वास्थ्य विभाग

प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य के सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाऐं उपलब्ध हैं तथा सर्पदंश की दवाईयाँ जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। प्रभारी प्रधान सचिव, पूर्वी चम्पारण के द्वारा बताया गया कि मोतिहारी में सर्पदंश की दवा की और आवश्यक्रता है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि सर्पदंश की दवा एवं अन्य आवश्यक दवाओं की स्थिति पर सतत् निगरानी की जाए तथा पूर्वी चम्पारण को और सर्पदंश की दवा उपलब्ध करा दी जाए।

10. <u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह तक चालू नलकूपों की संख्या 4353 है जबकि पिछले सप्ताह में चालू नलकूपों की संख्या 4316 थी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II)...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ कृषि विभाग/ सहकारिता विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना/ आयुक्त, पटना नगर निगम/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II) 2795 –/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 22/7/16.

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव